

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2014/भाद्र 31, 1936 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 104
No. 122] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2014/BHADRA 31, 1936 [N.C.T.D. No. 104

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

(कृषि विपणन निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2014

सं. एफ. 8(41)/2014/डीएम/एम आर/2156.—दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 के दिल्ली अधिनियम सं.-07) की धारा 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) ये नियम दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य (संशोधन) नियम, 2014 कहलाएंगे।
(2) ये दिल्ली गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. नियम 17 का संशोधन:— दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम 17, के उप नियम (1) के खण्ड (च) को हटाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

वी. पी. राव, विशेष सचिव (विकास)

DEVELOPMENT DEPARTMENT
(DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING)
NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2014

No. 8(41)/2014/DAM/MR/2156.—In exercise of the powers conferred by section 116 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 07 of 1999), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rules, 2000, namely :—

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Amendment of rule 17.** - In the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rules, 2000, in rule 17, in sub rule (1), clause (f) shall be omitted.

By Order and in the name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

V. P. RAO, Spl. Secy. (Development)

सामान्य प्रशासन विभाग
(समन्वय शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2014

सं.फा. 29/2/2008/सा.प्र.वि./समन्वय/dsgadIII/2525-2573.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल समस्त सरकारी कार्यालयों तथा स्थानीय/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक केन्द्र के उपक्रमों में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014, बृहस्पतिवार को अपराह्न 2.00 बजे के पश्चात् "फूल वालों की सैर" के उपलक्ष में आधे दिन का अवकाश घोषित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
अमिताभ कुन्दू, उप सचिव
(सा.प्रा.वि./सम.)

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2014

No. F. 29/2/2008/GAD/CN/dsgadIII/2525-2573.—The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare **Thursday, the 16th October, 2014** as a half day Holiday after 2.00 P.M. in all Government offices and Local/Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings under the Government of National Capital Territory of Delhi, on account of 'PHOOL WAALON-KI-SAIR'.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

AMITABH KUNDOO, Dy Secy. (GAD)

राजस्व विभाग
(कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण)
अधिसूचना
दिल्ली, 22 सितम्बर, 2014

संख्या एफ (953)/पं.शा./मंआ/मुख्याव/2014/5943.—दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 47क तथा धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 1961 की अधिसूचना का.आ. 1726 (संख्या एफ. 2/5/61—न्यायिक-2) 07 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना का.आ. 2709 (41/2/66—दिल्ली) के साथ पठित दिल्ली स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 2007 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा इस सरकार की दिनांक 04.12.2012 की अधिसूचना संख्या एफ (152)/पं.भा./मंआ/मुख्याव/2011/780 के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के प्रयोजन एवं आशय हेतु दिल्ली में भूमि तथा अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम दरों (सर्कल रेट) को संशोधित तथा अधिसूचित करते हैं, जैसा कि इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

उपरोक्त दरें दिल्ली में भूमि तथा अचल सम्पत्तियों के लिखत के पंजीकरण के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के उपबन्धों के अनुसार उन सभी पंजीयक अधिकारियों द्वारा लिखत के पंजीकरण के समय ध्यान में रखी जाएगी, जो उनके सामने अधिकार क्षेत्र होने के कारण दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है।

ये संशोधित दरें 23.09.2014 से प्रवृत्त होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजय कुमार, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

प्रथम परिशिष्ट-1

दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकरण के प्रयोजनों के लिये भूमि तथा सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम दरें (सर्कल रेट)

1. वाणिज्यिक औद्योगिक और अन्य प्रयोगों के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारण भूमि दरें:

तालिका-1

इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्गमीटर में)
ए	774000
बी	245520
सी	159840
डी	127680
ई	70080
एफ	56640
जी	46200
एच	23280

2. आवासीय प्रयोग हेतु न्यूनतम भूमि दरें:-

2.1 विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के अन्तर्गत भूमि का मूल्य ज्ञात करते समय आवासीय प्रयोग के लिये उक्त न्यूनतम भूमि दरों पर निम्नलिखित गुणक लागू होंगे :-

तालिका 1.1

प्रयोग*	सार्वजनिक सुविधाएं जैसे निजी विद्यालय/ महाविद्यालय/अस्पताल	औद्योगिक	वाणिज्यिक
गुणक	2	2	3

*एकक क्षेत्रफल संपत्ति कर पद्धति की परिभाषाओं की भांति

3. निर्माण लागत की न्यूनतम दरें:-

3.1. निर्माण की लागत की आधार एकक दर निम्न होगी:

तालिका 1.2

इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये न्यूनतम निर्माण दर (रुपये प्रति वर्गमीटर में)	वाणिज्यिक प्रयोग के लिये निर्माण की न्यूनतम दर (रुपये प्रति वर्गमीटर)
(1)	(2)	(3)
ए	21960	25200
बी	17400	19920
सी	13920	15960
डी	11160	12840
ई	9360	10800
एफ	8220	9480
जी	6960	8040
एच	3480	3960

3.2. संरचना की आयु पर विचार करने हेतु निम्नलिखित गुणक निर्माण की न्यूनतम लागत पर लागू होंगे:-

संपूर्ति वर्ष	1960 से पहले	1960-69	1970-79	1980-89	1990-2000	2000 से आगे
अवधि गुणक	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

3.3. विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के लिये उक्त न्यूनतम निर्माण लागत पर निम्नलिखित गुणक केवल 'जी' और 'एच' श्रेणियों की कॉलोनीयों के लिये ही विचाराणीय होंगे:-

ढांचा प्रकार	पक्का	अर्धपक्का	कच्चा
गुणक	1.0	0.75	0.5

4. चार तलों तक निर्मित फ्लैटों के लिये न्यूनतम दरें -

तालिका 1.3

कुर्सी तथा क्षेत्र के आधार पर फ्लैट की श्रेणी (वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोणियों/सहकारी समिति तथा सामूहिक आवास समितियों के लिये न्यूनतम निर्माण दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर) (आवासीय प्रयोग की स्थिति में)	दिल्ली विकास प्राधिकरण/ सामूहिक आवास समितियों/ निजी बिल्डरों द्वारा फ्लैट के लिये न्यूनतम निर्माण दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर) (वाणिज्यिक प्रयोग की स्थिति में)	निजी कालोनियों के लिये गुणक
30 वर्ग मीटर तक	50400	57840	1.10
30 से ऊपर तथा 50 वर्ग मीटर तक	54480	62520	1.15
50 से ऊपर तथा 100 वर्ग मीटर तक	66240	75960	1.20
100 वर्ग मीटर से ऊपर	76200	87360	1.25

4.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण/सहकारी/सामूहिक आवास सोसायटी के चार तलों से अधिक तलों फ्लैटों के लिए आवासीय प्रयोजनों के लिये 87840/- रुपये प्रति वर्गमीटर की एक समान दर निर्मित क्षेत्र की दर पर न्यूनतम मूल्य मान लिया जाएगा जबकि उस स्थिति में, जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये यही प्रयुक्त की जाती है तब वाणिज्यिक प्रयोग के लिये 100800/-रुपये प्रति वर्गमीटर की एक समान दर निर्मित क्षेत्र की दर पर न्यूनतम मूल्य मान लिया जाएगा। निजी बिल्डरों द्वारा बहुमंजिली फ्लैटों के लिये 1.25 का गुणक लागू होगा।

नोट-बेचे गए किसी फ्लैट से भिन्न किसी स्वतंत्र संपत्ति का भाग कुर्सी क्षेत्र अर्थात् एकतल, बेचे गए अनुपातिक कुर्सी क्षेत्रफल के लिये सम्बद्ध न्यूनतम भूमि लागत, और बेचे गए कुर्सी क्षेत्रफल पर लागू निर्माण की न्यूनतम लागत ली जा सकेगी।

REVENUE DEPARTMENT

(OFFICE OF THE CHIEF REVENUE CONTROLLER AUTHORITY)

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2014

No. F. 1(953)/Regn. Br./Div.Com./HQ/2014/5943.—In exercise of power conferred by sections 27 and 47A of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as in force in Delhi and in pursuance of the provision of rule 4 of the Delhi Stamp (Prevention of Under-valuation of Instruments) Rules, 2008, read with the Ministry of Home Affairs, Government of India S.O. 1736(No.F.2/5/61-Judl-II) dated the 22nd July, 1961 and Notification S.O. 2709 (41/2/66-Delhi), dated the 7th September, 1966 and in supersession of this Government's Notification No.F.1(152)/Regn. Br./Div.Com/ HQ/ 2011/780 dated the 4th December, 2012, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby revises and notifies, the minimum rates (Circle rates) for valuation of lands and immovable properties in Delhi for the purposes and intent of the said Act and the rules made thereunder, as specified in Annexure-I annexed to this notification.

The above rates, inter alia, shall be taken into consideration for registration of instruments relating to lands and immovable properties in Delhi by all the Registering Authorities under the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and the Indian Registration Act, 1908 (XVI of 1908) as in force in Delhi at the time of registration of instruments.

These revised rates shall come into force with effect from 23.09.2014.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR, Spl. Inspector General (Registration)

3802-4/14-2

ANNEXURE-1

Minimum Rates (Circle Rates) for valuation of land and properties for the purpose of payment of stamp duty under Indian Stamp Act as applicable to Delhi & registration fees under the Registration Act, 1908 in Delhi:—

1. Minimum land rate for Residential Use :-

Table-1.

Category of the locality	Minimum rates for valuation of land for residential use (in Rs. Per Sq. mtr.)
A	774000
B	245520
C	159840
D	127680
E	70080
F	56640
G	46200
H	23280

2. Minimum Land Rates for Commercial, Industrial and other uses :—

The following multiplying factors shall be employed to the above minimum land rates of residential use, to arrive at the cost of land under other following uses :—

Table-1.1

Use*	Public Utility e.g. private school, colleges, hospitals	Industrial	Commercial
Factor	2	2	3

*Definition are as per unit area property tax system

3. Minimum rates for cost of construction :—

3.1 The base unit rate of cost of construction will be :—

Table-1.2

Category of the locality	Minimum rates of construction for residential use (in Rs. Per Sq. mtr.)	Minimum rates of construction for Commercial use (in Rs. Per Sq. mtr.)
A	21960	25200
B	17400	19920
C	13920	15960
D	11160	12840
E	9360	10800
F	8220	9480
G	6960	8040
H	3480	3960

3.2 In order to take into account the age of structures, the following multiplying factor shall be employed to the minimum cost of construction mentioned above:—

Year of completion	Prior to 1960	1960-69	1970-79	1980-89	1990-2000	2000 onwards
Age factor	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

- 3.3 To calculate the valuation of different structures, the following multiplying factors to the above minimum cost of construction shall be employed under colonies in G and H category:

Structure Type	Pucca	Semi-Pucca	Katcha
Multiplicative	1.0	0.75	0.5

4. Minimum rates of built-up flats up to four storey :-

Table 1.3

Category of flats depending on plinth area (sq. Meters.)	Minimum built-up rate (in rupees per sq meters) for DDA colonies and group housing society (in case of residential use)	Minimum built-up rate (in rupees per sq meters) for DDA colonies/co-operative housing societies/ flats by private builder (in case of commercial use)	Multiplying factors for private colonies
Up to 30 sq meters	50400	57840	1.10
Above 30 and upto 50 sq meter	54480	62520	1.15
Above 50 and upto 100 sq meter	66240	75960	1.20
Above 100 sq meter	76200	87360	1.25

- 4.1 For the flats having more than four storeys, a uniform rate per sq. metre of Rs. 87840/- will be taken as a minimum value of built up rate for residential purpose. Whereas in case where the same is used for commercial purpose, a uniform rate per sq. metre of Rs. 100800/- will be taken as a minimum value of built up rate for commercial purpose. For multistories flats by flats by private builders, a multiplicative factor of 1.25 shall be employed.

Note : Where part plinth area, say one floor, of an independent property other than a flat is sold, the relevant minimum land cost may be taken for the proportionate plinth area sold, and minimum cost of construction applied on plinth area sold.